पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना ३)
हिमाचल प्रदेश राज्य

पर्यावरण आकलन दस्तावेज

प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षा

एडीबी ऋण संख्या. ३२२३-IND
परियोजना संख्या: ४०६४८

अंश ३

उप-परियोजना: नगरोटा बगवां, कांगड़ा में चामुंडा मंदिर और बज्रेश्वरी मंदिर की पुनर्स्थापना और सांस्कृतिक कला और शिल्प कला केंद्र का निर्माण और सुधार (पैकेज एचपीटीडीबी/ १३/४)

जून, २०१६

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार

यह आईईई उधारकर्ता का दस्तावेज है। यह जरूरी नहीं की इसमें व्यक्त विचार एडीबी के निदेशक मंडल, प्रबंधन या कर्मचारियों के हो।

कार्यकारी सारांश

१. पृष्ठभूमि. पर्यटन वित्तपोषण सुविधा (सुविधा) के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु के चार भाग लेने वाले राज्यों में बुनियादी शहरी ढांचे और सेवाओं का विकास और सुधार करेगा, जो आर्थिक विकास के लिए प्रमुख चालक के रूप में पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करेगा। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा: (१) प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच संपर्क को मजबूत करना; (२) बुनियादी शहरी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सड़क और सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मौजूदा और उभरते पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण में सुधार, ताकि आगंतुकों के लिए शहरी सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और प्रकृति और संस्कृति-आधारित आकर्षणों की रक्षा की जा सके; (३) पर्यटन स्थलों के बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित क्षेत्र की एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, और क्रमशः पर्यटन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

२. कांगड़ा जिले में चामुंडा मंदिर अक्षांश (३२'.१८'') और देशांतर (७६'.४५'') पर स्थित है। मंदिर पालमपुर के पश्चिम में लगभग १० किमी (६.२ मील) पर स्थित है। यह उस स्थान पर स्थित है जहाँ देवी महात्म्य में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। नजदीकी हवाई अड्डा संपर्क गग्गल (NH-20 के पास), कांगड़ा टाउन से लगभग 7 किमी दूर है।

३. बजरेश्वरी मंदिर एक धार्मिक स्थल है और हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। गंतव्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि यह सड़क के माध्यम से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कांगड़ा शहर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब से NH-88 (बिलासपुर – हमीरपुर - ज्वालाजी - कांगड़ा सहित शिमला) के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, NH-2O से (मंडी-पठानकोट) और होशियारपुर / जालंधर से धर्मशाला हाईवे जो ऊना जिले में चिंतपूर्णी के पास से गुजरते हुए जो अब कांगड़ा बाय-पास के रूप में नामित किया गया है। कांगड़ा एक संकीर्ण रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है जो जोगिंदर नगर तक है। निकटतम हवाई अड्डा गग्गल (NH-2O के पास) है जो कांगड़ा टाउन से लगभग 7 किमी दूर है।

४. चक्रकुंड, बजरेश्वरी मंदिर से लगभग १ किमी दूर स्थित है और इसमें दो पवित्र तालाब और कुछ छोटे मंदिर शामिल हैं।

५. माता का बाग अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) के तहत खाली पड़ी सरकारी जमीन है, जो कि चारदीवारी द्वारा सीमांकित है और वर्तमान में किसी भी उपयोग मैं नहीं है।

६. नगरोटा बगवां एक शहर और कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में एक नगर परिषद है। नगरोटा बगवां का अक्षांश ३२'.१०'' और देशांतर ७६'.३७'' है। २०११ की जनगणना के अनुसार, नगरोटा की जनसंख्या १९९९८

थी।

७. निष्पादन और कार्यान्वयन संगठन. निष्पादन संगठन हिमाचल प्रदेश की पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग है। परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना शिमला में समग्र निष्पादन को समन्वित करने के लिए किया गया है। शिमला में परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) निष्पादन में पीएमयू को सहायता प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसी, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन इकाई (पीइ) है, जिसे डिजाइन पर्यवेक्षण सलाहकार (डीएससी) द्वारा समर्थित किया जाना है। नगरोटा की संपत्ति का मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है और बजरेश्वरी और चामुंडा के मंदिर ट्रस्ट है। अनापत्ति प्रमाण पत्र का अधिग्रहण किया गया है और संबंधित परिसंपत्ति मालिकों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

८. वर्गीकरण. उप-परियोजना पैकेज एचपीटीडीबी/१३/४, को एसपीएस २००९ के अनुसार पर्यावरण श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की कल्पना नहीं की गई है। तदनुसार यह प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षा (आएईई) तैयार की गई है जो पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है और उप-परियोजना के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होने के लिए शमन और निगरानी के उपाय प्रदान करती है।

९. उप-परियोजना विषय क्षेत्र. इस उप-परियोजना पैकेज के लिए काम की प्रमुख गुंजाइश,

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार एचपीटीडीबी /१३/४ चामुंडा मंदिर, बजरेश्वरी मंदिर की बहाली और सुधार है। सामुदायिक आधारित पर्यटन और आजीविका पीढ़ी के संदर्भ में नगरोटा बगवां में पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं प्रदान करना। मुख्य काम हैं

i. चामुंक्ला मंदिर: भूनिर्माण, शौचालय और स्नान की सुविधा, आगंतुक तालाब के पास कमरे, पीने के पानी की सुविधा, १५० व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था, पवित्र मंदिर तालाब की बहाली और सड़क में सुधार, रेलिंग, निर्देशक और स्ट्रीट लाइटिंग का प्रावधान।
ii. बजरेश्वरी मंदिर: रेलिंग, निर्देशक और स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था में सुधार, पार्क का लैंडस्केपिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और टॉयलेट और नहाने की सुविधाओं, पीने के पानी की सुविधाओं और १०० व्यक्तियों के लिए समुचित बैठने की व्यवस्था जैसी
उन्नयन सुविधाएं।
iii. नगरोटा बगवां: वाणिज्यिक आउटलेट, स्थायी आउटलेट, अस्थायी आउटलेट, उत्पादों को दिखाने और बेचने; फूड स्टॉल (२५ अस्थाई स्टाल), कन्वेंशन हॉल (क्षमता २५० लोग), खाने की दुकान; & ओ.ए.टी; प्रवेश द्वार पर पार्किंग का निर्माण (२ मंजिल); बैठने की व्यवस्था के साथ केंद्र और भूनिर्माण उद्यान के लिए मिश्रित दीवार और प्रवेश द्वार का निर्माण।

iv. चक्रकुंड मंदिर: मौजूदा कुंड (तालाब), शौचालय और स्नानघर, मार्ग, क्षेत्र प्रकाश, बेंच और जल निकासी की बहाली।

v. माता का बैग: प्रस्तावित कार्य आगंतुकों को शौचालय, पार्किंग, दुकानें, अखाड़ा, बेंच, प्रकाश व्यवस्था, परिसर की दीवार, निर्देशक, डस्ट बिन और भूनिर्माण आदि जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

१०. पर्यावरण का वर्णन. उप-परियोजना कांगड़ा जिले में स्थित है जो ३१°२१' से ३२°५७' एन अक्षांश और ७५°४७'५५ " से ७७°४५' ई देशांतर के बीच स्थित है। यह हिमालय के दक्षिणी भाग पर स्थित है। जिले का पूरा क्षेत्र उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व तक शिवालिकों, धौलाधार और हिमालय से घिरा है। समुद्र तल से ऊंचाई ५०० मीटर से ५००० मीटर तक है। यह उत्तर में चम्बा और लाहौल स्पीति द्वारा, दक्षिण में हमीरपुर और ऊना द्वारा, पूर्व में मंडी से और पश्चिम में पंजाब के गुरदासपुर जिले से घिरा हुआ है। वर्तमान कांगड़ा जिला १ सितंबर, १९७२ को अस्तित्व में आया ।

११. पर्यावरण प्रबंधन. एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को आएईई के भाग के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं (१) कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों के लिए शमन उपाय; (२) एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम, और शमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार संस्थाएँ; (३) सार्वजनिक परामर्श और सूचना प्रकटीकरण; और (४) शिकायत निवारण तंत्र। डिजाइनों में संशोधन करके कई प्रभावों और उनके महत्व को पहले ही कम कर दिया गया है। ईएमपी को सिविल वर्क बिडिंग और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

१२. प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनाओं के स्थान और स्थलों पर विचार किया गया है। प्रस्तावित उप-परियोजना के डिजाइन में निम्नलिखित अवधारणाएं पर विचार किया गया है (१) डिजाइन, सामग्री और पैमाने स्थानीय वास्तुशिल्प, भौतिक, सांस्कृतिक और भूनिर्माण तत्वों के अनुरूप होंगी; (२) यथासंभव स्थानीय सामग्री और श्रम के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी; (३) संरक्षण के लिए, आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय निर्माण सामग्री का यथासंभव उपयोग किया जाएगा; (४) सभी पेंटिंग कार्य (आंतरिक और बाहरी) पर्यावरण के अनुकूल कम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पेंट के साथ होंगे; (५) दीवार की मरम्मत के काम के लिए, स्थानीय कुशल श्रम द्वारा सीमेंट मोर्टार में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्थर के साथ यादृच्छिक मलबे की चिनाई का उपयोग किया जाएगा; (६) यदि बैक फिलिंग की आवश्यकता होगी, तो यह साइट से खोदी गई सामग्री द्वारा की जाएगी; और (७) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइट चयन के लिए सभी योजना, डिजाइन और निर्णय सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण से इनपुट को प्रतिबिंबित करके और स्थानीय समुदायों के परामर्श से लिए जाएं।

१३. निर्माण के चरण के दौरान, वनस्पति के नुकसान का जोखिम मुख्य रूप से बेकार मिट्टी और विध्वंस सामग्री की मात्रा के निपटान की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। यह शहरी क्षेत्रों में निर्माण का सबसे आम

प्रभाव है, उनके शमन के लिए अच्छी तरह से विकसित तरीकों को लागू किया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि निर्माण कार्य ऐसे समय में किए जाएं जब कोई फसल न उगाई जाती है और किसी भी असुविधा को कम करने के लिए सर्वोत्तम निर्माण विधियों को नियोजित किया जाए। परिचालन चरण में, सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे नियमित रखरखाव के साथ काम करेंगे, जिससे पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़े। मरम्मत का काम भी समय-समय पर किया जाएगा। इस वजह से पर्यावरण पर प्रभाव बहुत कम होगा क्योंकि निर्माण कार्य नियमित नहीं होगा और इस तरह केवल छोटे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा।

१४. सभी नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं। निर्माण के दौरान किए जाने वाले पर्यावरण निगरानी के एक कार्यक्रम द्वारा, शमन सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपायों को लागू किया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि पर्यावरण अच्छी तरह से संरक्षित है या नहीं। इसमें साइट पर और ऑफ-साइट दस्तावेज़ जांच, श्रमिकों और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार शामिल होंगे। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं पर एडीबी को सूचित किया जाएगा।

१५. आईईई को हितधारकों द्वारा औन-साइट चर्चा और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से विकसित किया गया था। व्यक्त किए गए विचार आईईई में और उप-परियोजना की योजना और विकास में शामिल किए गए थे। आईईई को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए एडीबी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन वेबसाइटों का उपयोग किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परामर्श प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और उसमें विस्तार किया जाएगा ताकि हितधारक परियोजना में पूरी तरह से व्यस्त रहे तथा इसके विकास और कार्यान्वयन में भाग लेने का पूरा अवसर हो।

१६. शिमला क्षेत्र के पर्यटक, व्यवसायी और नागरिक इस परियोजना के प्रमुख लाभार्थी होंगे। शहर के पर्यटकों और आबादी के लिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य पर्यावरणीय लाभ, सकारात्मक और बड़े होंगे क्योंकि प्रस्तावित उप-परियोजना विश्वसनीय और पर्याप्त पर्यटन सुविधाओं तक पहुंचने में सुधार करेगी और राज्य की स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करेगी। यह उप-परियोजना स्थानीय परंपराओं और मूल्यों के लिए एक सामान्य मंच भी प्रदान करेगी, जो स्थानीय समुदायों के लिए व्यावसायिक अवसरों को प्रदान करने और सुधारने के लिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर्यटन से जुड़ी होगी।

१७. परामर्श, प्रकटीकरण और शिकायत निवारण. परियोजना और आएईई की तैयारी में सार्वजनिक परामर्श किया गया था। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान भी नियमित परामर्श होंगे। एक शिकायत निवारण तंत्र आईईई के भीतर परिभाषित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सार्वजनिक शिकायतों को जल्दी से दूर किया जाए।

१८. निगरानी और रिपोर्टिंग. पर्यावरण निगरानी के लिए पीएमयू, पीआईयू, पीएमसी और डीएससी जिम्मेदार होंगे। डीएससी के साथ समन्वय में पीआईयू मासिक निगरानी रिपोर्ट पीएमयू को प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार

पर पीएमयू एडीबी द्वारा ईएमपी के कार्यान्वयन पर अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वे एडीबी को पर्यावरण समीक्षा मिशनों की अनुमति भी देंगे ताकि पर्यावरण के अनिश्चित पहलुओं की समीक्षा की जा सके। एडीबी अपनी वेबसाइट पर पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट पोस्ट करेगा। एडीबी अपनी वेबसाइट पर पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट पोस्ट करेगा। गंभीर पर्यावरणीय परिणामों वाले किसी भी बड़े हादसे की सूचना तुरंत दी जाएगी। पीएमसी पर्यावरण विशेषज्ञ पर्यावरणीय समापन रिपोर्ट सहित त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगे।

१९. निष्कर्ष और सुझाव. प्रस्तावित उप-परियोजना के कारण कोई महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़े संभावित प्रभावों को उचित इंजीनियरिंग डिजाइन और अनुशंसित शमन उपायों और प्रक्रियाओं के निगमन या आवेदन के माध्यम से कठिनाई के बिना मानक स्तर तक कम किया जा सकता है। आईईई के निष्कर्षों के आधार पर, उप-परियोजना का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यह वर्गीकरण की श्रेणी बी में आता है। कोई और विशेष अध्ययन या विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), एडीबी एसपीएस - १००९ या भारत सरकार ईआईए अधिसूचना १००६ के अनुपालन के लिए किए जाने की आवश्यकता नहीं है।